



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 200]

नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 23, 1976/कार्तिक 1, 1898

No. 200]

NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 23, 1976/KARTIKA 1, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Roads Wing)

RESOLUTION

New Delhi, the 21st October 1976

No. PL-10(95)/76.—In their hundred and first report on Border Roads, the Estimates Committee (1975-76) of the Fifth Lok Sabha recommended that a Master Plan for the construction of roads in each of the States in the border areas should be drawn up with proper perspective and priorities after a critical assessment in depth of the requirements for roads in each of the concerned States. The Government of India have accepted this recommendation and have consequently decided to set up a Group for this purpose with the following compositions:—

Chairman

1. Director General (Road Development) and Additional Secretary, Ministry of Shipping and Transport, (Roads Wing).

Members

2. Joint Secretary, (dealing with Roads), Planning Commission.
3. Joint Secretary (N.E.) Ministry of Home Affairs,
4. Joint Secretary, Plan Finance, Ministry of Finance.

(1553)

5. Joint Secretary (G) Ministry of Defence.
6. Director, Military Operations, Army Headquarters.
7. Secretary, North Eastern Council, Shillong.

Member-Secretary

8. Secretary, Border Roads Development Board.

In addition, Chief Engineer, Planning (Roads Wing), Ministry of Shipping and Transport, would function as Joint Secretary of the Group.

2. The terms of reference of the Group will be as follows:—

- (a) To evolve a Master Plan for the development of road communications in the Border States keeping in mind the requirement of State Governments, requirement of National Highways, requirement for operational and strategic considerations, requirement for economic and industrial development and the special requirements of an area. The Master Plan would be a Perspective Plan of at least 15 years span and would also contain the programme that would be executed in the five years of the next Plan and in the subsequent Five Year Plans;
- (b) Having evolved the said Master Plan, to indicate the roads/Highways which would be developed in the State Plans and those roads/Highways which may be financed under the various Central Sector Schemes for road development; and
- (c) Having indicated the programmes under which the various roads would be taken up, indicate the agency for execution of the various programmes keeping in mind that the Border Roads Organisation should be made the primary agency for execution of Central Sector Road Development Schemes.

3. The Headquarters of the Group will be at Delhi but it will be free to visit such places as it may consider necessary in connection with its work. The Central Government hope that the State Governments and Local Administrations concerned will afford the Group all assistance it may require and furnish any information which it may call for.

4. The Group will submit its report within a period of one year.

ORDER

Ordered that copies of the Resolution be communicated to all the Border States/Local Administrations, Planning Commission, Ministry of Home Affairs, Ministry of Finance (Plan Finance Division), Ministry of Defence, D.M.O., Army Headquarters, Secretary, North Eastern Council, Shillong and Secretary, Border Roads Development Board and also that it be published in the Gazette of India for general information.

J. S. MARYA,

Director General (Road Development)
and Addl. Secy.

नौबहत और परिवहन मंत्रालय

(सड़क पक्ष)

संकल्प

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर 1976

सं० पी एल-10(95)/76.—पीमा सड़कों पर अपनी 101 बोरिपोर्ट में पांचवीं लोक सभा के प्राक्कला समिति (1975-76) ने सिफारिश की कि पीमा क्षेत्र वाले राज्यों में से प्रत्येक में सड़कों की आवश्यकता की गहन रूप से सूक्ष्म मूल्यांकन करने के बाद उचित दृश्य और प्राथमिकता के साथ संबन्धित राज्यों में से प्रत्येक में सड़कों के निर्माण के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जाए। भारत सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है और फलस्वरूप

इस योजना के लिए एक दल स्थापित करने का निश्चय किया जिसका गठन निम्न प्रकार होगा :—

अध्यक्ष

1. महानिदेशक (सड़क विकास) और अपर सचिव,
नौवहन और परिवहन मंत्रालय (सड़क पक्ष)

सदस्यगण

2. संयुक्त सचिव, (सड़कों से सम्बन्धित) योजना आयोग
3. संयुक्त सचिव (एन० ई०), गृह मंत्रालय
4. संयुक्त सचिव, योजना वित्त, वित्त मंत्रालय
5. संयुक्त सचिव (जी), रक्षा मंत्रालय
6. निदेशक, सेना संचालन, शस्त्र सेना मुख्यालय
7. सचिव, उत्तर पूर्वी परिषद्, शिलोंग

सदस्य सचिव

8. सचिव, सीमा पथ विकास बोर्ड

इसके अलावा मध्य इंजीनियर, योजना (सड़क पक्ष) नौवहन और परिवहन मंत्रालय दल के संयुक्त सचिव के रूप में कार्य करेंगे ।

2. दल के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे .—

- (क) राज्य सरकारों की आवश्यकताओं, राष्ट्रीय राजमार्ग की आवश्यकताओं, संचालन और सामरिक विचार की आवश्यकताओं, आर्थिक और औद्योगिक विकास की आवश्यकताओं और क्षेत्र की विशेष आवश्यकताओं की दृष्टि में रखते हुए सीमा क्षेत्र वाले राज्यों में सड़क संचार के विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार करना/मास्टर प्लान कम से कम 15 वर्ष की अवधि की दृष्टि योजना होगी और जिसमें वह कार्यक्रम भी होगा जो आगामी योजना के पांच वर्षों में और बाद के पंचवर्षीय योजनाओं में किया जायेगा ।
- (ख) उक्त मास्टर योजना तैयार करके वे सड़कों/राज्यमार्ग दर्शना जिनका राज्य योजनाओं में विकास किया जाएगा और वे सड़कों/राजमार्ग जिनका सड़क विकास के लिए विभिन्न केन्द्रीय सेक्टर योजनाओं के अधीन वित्त पोषित किया जा सकता है ; और
- (ग) ऐसे कार्यक्रम दिखाकर जिनके अधीन विभिन्न सड़क कार्य शुरू किये जायेंगे, विभिन्न कार्यक्रमों के निष्पादन के लिए यह बात ध्यान में रख कर एजेंसी बताना कि केन्द्रीय क्षेत्र सड़क विकास योजनाओं के निष्पादन के लिए सीमा सड़क संगठन को मुख्य एजेंसी बनाया जाए ।

3. दल का मुख्यालय दिल्ली में होगा । परन्तु वह ऐसे स्थानों में भी जा सकते हैं जो वह अपने कार्य के सम्बन्ध में आवश्यक समझेगा । केन्द्रीय सरकार को यह आशा है कि सम्बन्धित राज्य सरकारें और स्थानीय प्रशासन दल को वे सभी सहायताएं देगे जिनकी उसे आवश्यकता होगी और ऐसी कोई भी सूचना देगे जो वह मागे ।

4. दल अपनी रिपोर्ट एक वर्ष के भीतर प्रस्तुत करेगा ।

प्रादेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रतियां सभी सीमान्त राज्यों/स्थानीय प्रशासनों, योजना आयोग, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय (योजना वित्त प्रभाग), रक्षा मंत्रालय, डी०एम० ओ०, सेना मुख्यालय, सचिव, उत्तर पूर्वी परिषद्, शिलांग और सचिव सीमा पथ विकास बोर्ड को भेज दी जाए और यह भी कि इसे आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

जगदेव सिंह मड़िया,

महा निदेशक (सड़क विकास) तथा अपर सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा
नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976